अध्याय – 7
राजस्थान का आर्थिक विकास

योजनाबद्ध विकास

राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए 1951 से योजनाबद्ध विकास का प्रारम्भ पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किया गया। वर्तमान में राज्य में योजनाबद्ध विकास को प्रारंभ हुए 62 वर्ष पूरे हो गये है। इस समयावधि में ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं तथा छह वार्षिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 54.2 करोड़ रूपये था जो बढ़कर दसवीं पंचवर्षीय योजना में 33735.1 करोड़ रूपये हो गया। राजस्थान में 1951–52 से लेकर 2006–07 तक (पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक) 74650.5 करोड़ रूपये व्यय किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित उद्व्यय 71732 करोड़ रूपये है। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में जहां राजस्थान कृषि में पिछड़ापन, अकाल एवं सूखा, औद्योगिक पिछड़ापन, ऊर्जा का अभाव, निर्धनता आदि समस्याओं से जूझ रहा था। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत तथा सिंचाई विकास को प्राथमिकता दी गई। वर्तमान में राज्य सरकार सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किये हुए है। राज्य की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में किया गया वास्तविक व्यय तालिका 7.1 से स्पष्ट है–

तालिका 7.1 राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपए)

योजना	योजना अवधि	वास्तविक व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना	(1951-56)	54.15
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	(1956-61)	102.74
तृतीय पंचवर्षीय योजना	(1961-66)	212.70
वार्षिक योजनाएं	(1966-69)	136.76
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	(1969-74)	308.79
पांचवी पंचवर्षीय योजना	(1974-79)	857.62
वार्षिक योजना	(1979-80)	290.19
छठी पंचवर्षीय योजना	(1980-85)	2120.45
सातवीं पंचवर्षीय योजना	(1985-90)	3106.18
वार्षिक योजना	(1990-92)	2159.98
आठवीं पंचवर्षीय योजना	(1992-97)	11998.97
नवी पंचवर्षीय योजना	(1997-02)	19566.82
दसवीं पंचवर्षीय योजना	(2002-07)	33735.14
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	(2007-12)	71731.98
दसवीं पंचवर्षीय योजना (अनुमोदित उद्व्यय)	(2012-17)	194283.44

स्त्रोत : आर्थिक समीक्षा 2008–09, राजस्थान सरकार पृ. 18, योजना आयोग भारत सरकार

योजना परिव्यय और प्राथमिकताएं – राजस्थान में 1951–52 से लेकर 2006–07 की समयावधि में दस पंचवर्षीय योजनाएं सम्पन्न हो चुकी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007–12 है। योजनाबद्ध विकास के इन छह दशकों (1951–2010) में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ कुछ वार्षिक योजनाएं भी महत्वपूर्ण रही। इनमें 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1979–80, 1990–91 तथा 1991–92 उल्लेखनीय है। राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं से सार्वजनिक व्यय और प्राथमिकताएं निम्नलिखित है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) – राज्य में योजनाबद्ध विकास की शुरूआत एक अप्रेल 1951 से हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि एक अप्रेल 1951 से 31 मार्च 1956 थी। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 54.15 करोड़ रूपये था। इस योजना में कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 2.6 करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पर 3.3 करोड़ रूपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 31.3 करोड़ रूपये, ऊर्जा पर 1.2 करोड़ रूपये, उद्योग व खनिज पर 0.5 करोड़ रूपये, यातायात पर 5.6 करोड़ रूपये तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 9.7 करोड़ रूपये खर्च किये गये। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की भांति राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) – इस योजना की समयावधि एक अप्रेल 1956 से 31 मार्च 1961 थी। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 102.74 करोड़ रूपये था। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 27.9 करोड़ रूपये तथा ऊर्जा पर 15.2 करोड़ रूपये खर्च किये गये। इस योजना में भी सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में इस योजना में ऊर्जा विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) – इस पंचवर्षीय योजना की समयावधि एक अप्रेल 1961 से 31 मार्च 1966 थी। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 212.70 करोड़ रूपये था। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर सबसे अधिक 87. 9 करोड़ रूपये खर्च किया गया। इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 43.1 करोड़ रूपये तथा ऊर्जा पर 39. 4 करोड़ रूपये व्यय किये गये। योजना में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा ऊर्जा विकास पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया।

तीन वार्षिक योजनाएं (1966–69) – उल्लेखनीय है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि में भारत को दो विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। भारत पर 1961 में चीन ने तथा 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में वित्तीय संसाधनों के अभाव में चौथीं पंचवर्षीय योजना देश में नियत समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। एक–एक वर्ष की तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई। राजस्थान में भी 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 तीन वार्षिक योजनाएं बनी। इन तीनों योजनाओं का वास्तविक व्यय 136.76 करोड़ रूपये था। तीनों वार्षिक योजनाओं में ऊर्जा विकास पर 46.8 करोड़ रूपये व्यय किया गया। वार्षिक योजनाओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) – इस पंचवर्षीय योजना की समयावधि एक अप्रेल 1969 से 31 मार्च 1974 थी। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 308.79 करोड़ रूपये था। योजनावधि में ऊर्जा पर 94 करोड़ रूपये तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 72.4 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। इस योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय में भारी वृद्धि हुई। इस विकास शीर्ष पर व्यय बढ़कर 105.3 करोड़ रूपये पहुँच गया।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) – इस पंचवर्षीय योजना की समयावधि एक अप्रेल 1974 से 31 मार्च 1979 थी। योजना का सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 857.62 करोड़ रूपये था। ऊर्जा विकास पर 249 करोड़ रूपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 217 करोड़ रूपये, सामाजिक एवं आर्थिक

सेवाओं पर 150 करोड़ रूपये व्यय किया गया। योजना में ऊर्जा विकास पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया।

वार्षिक योजना (1979–80) – वित्त वर्ष 1979–80 को वार्षिक योजना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पीछे कारण राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक बदलाव की स्थिति थी। वार्षिक योजना 1979–80 का सार्वजनिक क्षेत्र वास्तविक व्यय 290.19 करोड़ रूपये था।

छठी पंचवर्षीय योजना(1980–85) – इस योजना की समयावधि एक अप्रेल 1980 से 31 मार्च 1985 थी। योजना का सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 2120.45 करोड़ रूपये था। योजनावधि में ऊर्जा विकास पर 566 करोड़ रूपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 553 करोड़ रूपये, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 422 करोड़ रूपये खर्च किया गया। योजना में ऊर्जा विकास पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) – इस योजना की समयावधि एक अप्रेल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही। वास्तविक योजना परिव्यय 3106.8 करोड़ रूपये था। ऊर्जा विकास शीर्ष पर 928 करोड़ रूपये व्यय किया जो कुल योजना परिव्यय का 29.9 प्रतिशत था। ऊर्जा के बाद सबसे अधिक व्यय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर 788.7 करोड़ रूपये तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 691 करोड़ रूपये व्यय किया गया। योजना में सर्वाधिक ध्यान ऊर्जा विकास पर केन्द्रित किया गया।

वार्षिक योजनाएं (1990–92) – वित्त वर्ष 1990–91 और 1991–92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में स्वीकार किया गया। इन दोनों वार्षिक योजनाओं का वास्तविक व्यय 2159.98 करोड़ रूपये था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) – आठवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि एक अप्रेल 1992 से 31 मार्च 1997 तक थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 11998.97 करोड़ रूपये था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में भारी बढ़ोतरी की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार, अब तक सम्पन्न हो चुकी सात पंचवर्षीय योजनाओं के सम्मिलित आकार से भी बड़ा था। पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास शीर्ष पर 3254 करोड़ रूपये व्यय किया गया जो कुल योजना परिव्यय का 27.1 प्रतिशत था। सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर 3168 करोड़ रूपये (कुल परिव्यय का 26.4 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 1836 करोड़ रूपये (कुल परिव्यय का 15.3 प्रतिशत) व्यय किया गया। इस योजना में ऊर्जा विकास शीर्ष पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) – नवीं योजना की समयावधि एक अप्रेल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। नवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को बनाये रखना था। नवीं योजना के अन्य उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास, क्षेत्रीय विषमता में कमी, राजकोषीय घाटे को कम करना आदि प्रमुख है।

भारत के योजना आयोग द्वारा राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित प्रारूप प्रचलित कीमतों पर 27650 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया था। इसमें से सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, पर अनुमोदित उद्व्यय 7519 करोड़ रूपये था जो कुल उद्व्यय का 27.2 प्रतिशत था।

नवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित उद्व्यय 27650 करोड़ रूपये के मुकाबले वास्तविक उद्व्यय 19566.82 करोड़ रूपये रहा। इस योजना में अनुमोदित उद्व्यय का 70.77 प्रतिशत भाग ही व्यय किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि राज्य की नवीं योजना के आकार में भारी कटौती हुई। देश में 1996–97 के बाद की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव योजनाबद्ध विकास पर पड़ा। केन्द्र में 1996 से लेकर 1999 तक बार–बार सरकार बदलने से नवीं योजना का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो सका। नवीं योजनावधि के प्रारंभिक दो वर्ष में योजना क्रियान्वयन गति नहीं पकड़

सका था। केन्द्र सरकार ने अगस्त 1999 में नवीं योजना के उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप बदलें।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) – दसवीं योजना की समयावधि एक अप्रेल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का राष्ट्रीय उद्देश्य उन समस्याओं को सुलझाना था जो अभी तक यथावत थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सितम्बर 2001 की बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में योजना आयोग द्वारा निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे :

1. गरीबी 2007 तक 5 प्रतिशत तथा 2012 तक 15 प्रतिशत कम करना है।
2. उच्च गुणात्मक रोजगार अवसरों का सृजन।
3. वर्ष 2003तक सभी बच्चों को स्कूल भेजकर वर्ष 2007 तक उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करना।
4. साक्षरता एवं मजदूरी में 2007 तक लिंग भेद 50 प्रतिशत कम करना।
5. 2001 व 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 16.2 प्रतिशत तक करना।
6. योजना अवधि में साक्षरता दर बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करना।
7. वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर कम कर प्रति हजार 45 करना।
8. वर्ष 2007 तक मातृ मृत्यु दर कम कर प्रति हजार 2 तथा 2012 तक 1 करना।
9. वर्ष 2007 तक वन क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा 2012 तक 33 प्रतिशत वृद्धि करना।
10. योजना अवधि में सभी गांवों को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
11. वर्ष 2007 तक सभी मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।

राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक उद्व्यय प्रचलित कीमतों पर 33735.14 करोड़ रूपये था। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं उद्व्यय 10196.95 करोड़ रूपये था जो कुल उद्व्यय का 30.23 प्रतिशत था। ऊर्जा विकास शीर्ष पर उद्व्यय 10461.46 करोड़ रूपये था जो कुल उद्व्यय का 31.01 प्रतिशत था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित उद्व्यय 31831.75 करोड़ रूपये के मुकाबले वास्तविक उद्व्यय 33735.14 करोड़ रूपये रहा। उल्लेखनीय है जहाँ नवीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित उद्व्यय को पूरा नहीं कर सकी, वहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अनुमोदित उद्व्यय 31831.75 करोड़ रूपये की तुलना में वास्तविक व्यय 33735.14 करोड़ रूपये रहा। दसवीं योजना का आकार अनुमोदित उद्व्यय की तुलना में 5.98 प्रतिशत अधिक था।

राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

वर्तमान में राजस्थान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। इसकी समयावधि एक अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 71731.98 करोड़ रूपये अनुमोदित की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्व्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है। ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय 71731.98 करोड़ रूपये दसवीं योजना में अनुमोदित उद्व्यय31831.75 करोड़ की तुलना में 39900.23 करोड़ रूपये अधिक है। ग्यारहवीं योजना अनुमोदित उद्व्यय के हिसाब से दसवीं योजना के 2.25 गुना अधिक है।

ग्यारहवीं योजना के वृद्धि लक्ष्य : राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत, उद्योग वृद्धि दर 8 प्रतिशत तथा सेवा वृद्धि दर 8. 9 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये गये है। योजनावधि में राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की ग्यारहवीं योजना का अनुमोदित उदव्यय तालिका 7.2 द्वारा स्पष्ट है–

तालिका 7.2 राजस्थान की ग्यारहवीं योजना का अनुमोदित उद्व्यय

क्र.सं.	विकास शीर्ष	योजना उद्व्यय (करोड़ रूपये)	कुल उद्व्यय से प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	2269.07	3.16
2	ग्रामीण विकास	4295.14	5.99
3	विशिष्ट क्षेत्रीय विकास	1759.43	2.45
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7302.06	10.18
5	ऊर्जा	25606.75	35.70
6	उद्योग एवं खनिज	958.65	1.34
7	परिवहन	4683.06	6.53
8	वैज्ञानिक सेवाएं	29.70	0.04
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	19719.83	27.49
10	आर्थिक संवाएं	731.04	1.02
11	सामान्य सेवाएं	4377.25	6.10
	योग	**71731.98**	**100.00**

ग्यारहवीं योजना में ऊर्जा विकास शीर्ष पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस विकास शीर्ष का अनुमोदित उद्व्यय 25606.75 करोड़ रूपये है जो कुल योजना उद्व्यय का 35.70 प्रतिशत है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर उद्व्यय 19719.83 करोड़ रूपये है जो कुल योजना उद्व्यय का 27.49 प्रतिशत है। इनके अलावा कुल योजना उद्व्यय का कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 3.16 प्रतिशत, ग्रामीण विकास पर 5.99 प्रतिशत, विशिष्ट क्षेत्रीय विकास पर 2.45 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 10.18 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिज पर 1.34 प्रतिशत, परिवहन पर 6.53 प्रतिशत, वैज्ञानिक सेवाओं पर 0.04 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 1.02 प्रतिशत तथा सामान्य सेवाओं पर 6.10 प्रतिशत आवंटन किया गया है।

वार्षिक योजनाएं – राजस्थान में केवल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ही आकार में बड़ी नहीं है बल्कि इसकी वार्षिक योजनाओं का आकार भी उत्तरोत्तर बढ़ा है। वित्त वर्ष 2007–08 की वार्षिक योजना का आकार 13795 करोड़ रूपये, 2008–09 की वार्षिक योजना 14916 करोड़ रूपये तथा 2009–10 की वार्षिक योजना 17322 करोड़ रूपये थी। योजना आयोग, नई दिल्ली ने राजस्थान की 2010–11 की वार्षिक योजना का आकार 24000 करोड़ रूपये निर्धारित किया था। यह योजना 2009–10 की वार्षिक योजना 17322 करोड़ रूपये की तुलना में 38.55 प्रतिशत अधिक थी। वार्षिक योजना 2011–12 राजस्थान के योजनाबद्ध विकास के इतिहास की बड़ी वार्षिक योजना थी। इसका आकार 28461.30 करोड़ रूपये (प्रस्तावित) था।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17

योजना आयोग ने राजस्थान की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का आकार 194283.44 करोड़ रूपये तय किया है। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना राशि 71731.98 करोड़ रूपये से 170.85 प्रतिशत अधिक है। बारहवीं

पंचवर्षीय योजना एक अप्रेल 2012 से प्रारम्भ हो चुकी है। योजना आयोग के अनुसार राजस्थान पूरे प्रदेश में पहला राज्य है जिसकी बारहवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2012–13 सबसे पहले मंजूर की।

वार्षिक योजना 2012–13

वित्त वर्ष 2012–13 बारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वित्त वर्ष है। योजना आयोग ने राज्य की 2012–13 की वार्षिक योजना का आकार 33500 करोड़ रूपये तय किया है। यह 2011–12 की अनुमोदित वार्षिक योजना 28461.30 करोड़ रूपये की तुलना में 17.70 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2012–13 में सबसे अधिक उद्व्यय उर्जा के लिए निर्धारित किया गया है। सामुदायिक सेवाओं को भी प्रमुख प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। योजना आयोग ने राजस्थान की वार्षिक योजना 2012–13 के 33128 करोड़ रूपये प्रस्ताव की तुलना में अधिक निर्धारित किया है। राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2010–11 में 10.97 प्रतिशत भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत से ज्यादा थी।

योजनाबद्ध विकास की उपलब्धियां

राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस समयावधि में ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं सम्पन्न हो चुकी है। वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। योजनाबद्ध विकास में भारी पूंजी विनियोजन से राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राजस्थान अब ''बीमारू राज्य'' नहीं है। वर्तमान में राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था का विकासशील राज्य के रूप में उभरा है। राजस्थान के विकास की गति के बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास की उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं :

1. **सकल घरेलू उत्पाद** – राजस्थान ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। वर्ष 1991 के बाद राजस्थान ने भारत के बदलते आर्थिक परिवेश के साथ अर्थव्यवस्था को समायोजित किया। आर्थिक नीतियों में किये गये बदलाव और आधारभूत संरचना के विकास पर बल देने से राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 27 प्रतिशत है। यहाँ कृषि विकास मानसून पर भी निर्भर करता है। मानसून के अनुकूल होने की दशा में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ जाता है।

स्थिर कीमतों (1999–2000) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1980–81 में 26004 करोड़ रूपये था जो बढ़कर 2000–01 में 81060 करोड़ रूपये तथा 2005–06 में और बढ़कर 109107 करोड़ रूपये हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2004–2005) पर 2011–12 में 215454 करोड़ रूपये (अग्रिम अनुमान) था। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011–12 में 368320 करोड़ रूपये था।

2. **सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि दर** – राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर को गति मिली है। हाल के वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी 2008 का प्रभाव पड़ा है। वैश्विक मंदी के कारण 2008–09 में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2006–07 में उल्लेखनीय थी। इस वर्ष स्थिर कीमतों पर (1999–2000) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.81 प्रतिशत तथा प्रचलित कीमतों पर 15.73 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2010–11 में स्थिर कीमतों पर 9.69 प्रतिशत तथा प्रचलित कीमतों पर 18.83 प्रतिशत रह गई।

3. **प्रति व्यक्ति आय** – शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। विगत वर्षों में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है।

योजनाबद्ध विकास में प्रति व्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 1980–81 में 1619 रूपए थी जो बढ़कर 2000–01 में 13020 रूपए तथा 2005–06 में और बढ़कर 17997 रूपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 2011–12 में 47506 रूपए (अग्रिम अनुमान) हो गई। स्थिर (1999–2000) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1980–81 में 6200 रूपए थी जो बढ़कर 2000–01 में 12840 रूपए तथा 2005–06 में और बढ़कर 16460 रूपए हो गई। स्थिर कीमतों (2004–05) पर प्रति व्यक्ति आय 2011–12 में 27421 रूपये (अग्रिम अनुमान) हो गई।

4. **खाद्यान्न उत्पादन –** योजनाबद्ध विकास में कृषि के क्षेत्र में साठ के दशक में हरित क्रांति का लागू किया जाना महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण हरित क्रांति का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया। इसके बावजूद भी राजस्थान ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। खाद्यान्न उत्पादन में उतार–चढ़ाव अवश्य है।

खाद्यान्न उत्पादन 1950–51 में 29.4 लाख टन था जो बढ़कर 2000–01 में 100.4 लाख टन तथा 2006–07 में और बढ़कर 149.3 लाख टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन 2011–12 में 209.45 लाख टन (प्रावधानिक) था। कृषि उत्पादन सूचकांक 2005–06 में 153.84 तथा 2010–11 243.84 (प्रावधानिक) अंक था। खाद्यान्न उत्पादन के साथ तिलहन, गन्ना, और कपास का उत्पादन भी बढ़ा है। तिलहन का उत्पादन 1980–81 में 3.8 लाख टन, 2005–06 में 5. 9 लाख तथा 2007–08 में 4.2 लाख टन था। गन्ना उत्पादन 1980–81 में 11.6 लाख टन, 2005–06 में 4.8 लाख टन तथा 2007–08 में 5.9 लाख टन (अंतिम) था। कपास का उत्पादन 1980–81 में 66 हजार गाँठे से बढ़कर 2005–06 में 1.5 लाख गाँठे तथा 2007–08 में समान रहते हुए 1.5 लाख गाँठे रहा।

5. **सिंचाई** : राज्य में कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाएं आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई को अधिक प्राथमिकता दी गई है। परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1951–52 में 10 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 2000–01 में 49 लाख हैक्टेयर तथा 2005–06 में और बढ़कर 62.9 लाख हैक्टेयर हो गया। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2007–08 में 64.4 लाख हैक्टेयर था। सकल सिंचित क्षेत्र 2007–08 में 80.9 लाख हैक्टेयर था।

6. **विद्युत विकास**– आर्थिक विकास के लिए विद्युत महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। राजस्थान का आर्थिक विकास की दृष्टि से विगत में पिछड़े रहने का प्रमुख कारण विद्युत का अभाव था। राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। योजनाबद्ध विकास में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता (installed capacity) में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 1950–51 में केवल 8 मेगावाट थी जो बढ़कर 2000–01 में 3998 मेगावाट तथा 2005–06 में और बढ़कर 5454 मेगावाट हो गई। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसम्बर 2011 तक 9831 मेगावाट हो गई। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2002–03 में 291 किलोवाट था जो तेजी से बढ़कर 2005–06 में 572 किलोवाट हो गया। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1950–51 में केवल 3 युनिट था। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 2009 तक 37288 गाँवों को विद्युतीकृत एवं 8.96 लाख कुओं को ऊर्जीकृत किया गया।

7. **औद्योगिक विकास** – आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। योजनाबद्ध विकास में राज्य के औद्योगीकरण को गति मिली है। राज्य में योजनाबद्ध विकास के प्रारंभिक वर्षो में सूती वस्त्र, चीनी व वनस्पति घी की कुछ मीलें थी। वर्तमान में सूती व सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविजन, टायर ट्यूब, वनस्पति तेल, इंजीनियरिंग इकाइयां, खनिज आधारित बडी एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयां है।

राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1980–81 में 187 अंक था जो 2000–01 में बढ़कर 155 अंक तथा 2008–09 में और बढ़कर 263 अंक हो गया। वित्त वर्ष 2008–09 में विनिर्माण सूचकांक 262, खनिज सूचकांक 248, विद्युत सूचकांक 291 तथा औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक 263 था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1993–94) वर्ष 2011–12 में 337.73 (प्रावधानिक) था।

8. **परिवहन विकास** – परिवहन महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। सड़के और रेल्वे आर्थिक विकास के क्षेत्र में मानव शरीर में शिराएं और धमनियों की भाँति काम करती है। राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन पर भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किया गया। योजनाबद्ध विकास में सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण राज्य में परिवहन विकास को गति मिली है।

सड़कों की कुल लम्बाई 1980–81 में 41194 किलोमीटर थी जो 2008–09 में बढ़कर 186806 किलोमीटर हो गई। इनमें 1980–81 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2533 किलोमीटर था जो 2008–09 में बढ़कर 5714 किलोमीटर हो गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 39753 आबाद गाँव है। वर्ष 2008–09 तक 31834 गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया। डामर की सड़क से 80.08 प्रतिशत गांव जुड़े हुए है। मार्च 2008 में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 5683 किलोमीटर थी। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेलमार्गों की औसतन लम्बाई 16.61 किलोमीटर थी।

9. **सामाजिक विकास** – योजनाबद्ध विकास में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र यथा शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सामाजिक कल्याण, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि में सुधार हुआ है।

राज्य की साक्षरता दर 1951 में केवल 8.50 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2011 में 67.1 प्रतिशत हो गई। पुरूष साक्षरता में राजस्थान ने अच्छी प्रगति की है। पुरूष साक्षरता 2011 में 80.5 प्रतिशत थी जो अखिल भारत पुरूष साक्षरता 82.14 प्रतिशत से थोड़ी कम है जबकि राज्य में महिला साक्षरता दर 52.7 प्रतिशत हो गई है।

योजनाबद्ध विकास में अर्थव्यवस्था के सभी विकास शीर्षों में प्रगति हुई है। राजस्थान आर्थिक पिछड़ेपन से निजात पा चुका है, किन्तु अभी भी राज्य के आर्थिक विकास की गति को और तेज किये जाने की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण में वित्तीय संसाधन जुटाना कठिन नहीं है। वर्तमान में स्वदेशी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर विकास की गति को तेज किया जा सकता है।

नई औद्योगिक नीति

औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक विकास औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना चाहता है इसके लिए दिशा–निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है। अतः देश की औद्योगिक नीति उसके औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। वर्ष 1991 के बाद बदलते आर्थिक परिवेश में तो औद्योगिक नीति की उपयोगिता और भी बढ़ गई है।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

स्वतंत्रता के बाद घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समान रहे हैं। औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना होता है। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो। औद्योगिक नीति के द्वारा प्रायः सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है। औद्योगिक नीति संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है। इससे उद्योग, कृषि तथा अन्य विविध क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र,

निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों के अधिकार और दायित्वों का स्पष्ट विभाजन होता है।

बड़े और लघु उद्योगों का क्षेत्र विभाजित कर इन्हें परस्पर प्रतिस्पर्धी होने से बचाया जाता है। जिससे लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में फलने–फूलने का अवसर मिलता है। उपभोग वस्तु उद्योगों और पूंजी वस्तु उद्योगों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूंजी एवं साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है। प्रायः भारत जैसे विकासशील देशों में पूंजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा पूरी की जाती है।

औद्योगिक नीति

भारत में केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्रायः सभी राज्य आत्मसात करते हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रलोभन युक्त घोषणा करती है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति

राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। राजस्थान सरकार अपने स्तर पर स्वदेशी और विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति 1978, औद्योगिक नीति 1990, औद्योगिक नीति 1994 तथा औद्योगिक नीति 1998 घोषित की जा चुकी है।

राजस्थान में 1978 की औद्योगिक नीति तथा 1990 की औद्योगिक नीति योजनाबद्ध विकास के दौर में घोषित की गई। भारत में वर्ष 1991 से आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक नीति 1994 तथा औद्योगिक नीति 1998 घोषित की गई। राज्य सरकार ने इन औद्योगिक नीति का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा के आधार पर किया है। राजस्थान की 1994 की औद्योगिक नीति और 1998 की औद्योगिक नीति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के बदलते आर्थिक परिवेश के अनुसार समायोजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राजस्थान की नई औद्योगिक नीति 2010

राजस्थान के खनिजों का अजायबघर होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में विशेषकर औद्योगिक विकास में इस राज्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में आर्थिक उदारीकरण को प्रारंभ हुए पूरे दो दशक बीत चुके हैं। इस दौरान अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव आ चुके हैं। इस कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था को देश के बदलते आर्थिक पर्यावरण के साथ समायोजित करने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव की आवश्यकता थी। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2010 की घोषणा की। इस नई नीति की प्रमुख बातें निम्नांकित हैः

1. उद्देश्यः औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन और सेवा क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से उंची और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के साथ–साथ अनुकूल पर्यावरण और संतुलित विकास को ध्यान में रखा जाएगा। निजी क्षेत्र के निवेश और उद्यम को आकर्षित करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया है। इनके अलावा मानव संसाधन विकास और ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। बढ़ती युवा जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है।

2. व्यूहरचनाः औद्योगिक नीति के निर्धारित किये गये उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए व्यूहरचना तैयार की गई

है। व्यूहरचना का ध्येय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास करना तथा देशी और विदेशी निवेश में वृद्धि करना है। व्यूहरचना में व्यावसायिक पर्यावरण में सुधार, गुणवत्ता वाले आधारभूत ढांचे का विकास, परियोजनाओं के लिए भूमि की आसान उपलब्धता, रोजगार सृजन, सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों को प्रोत्साहन, चिन्हित थ्रस्ट क्षेत्रों का संवर्द्धन आदि को सम्मिलित किया गया है।

3. व्यावसायिक वातावरण में सुधारः राज्य सरकार व्यावसायिक वातावरण को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। व्यापार नियामक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। व्यावसायिक वातावरण सुधार के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम), नियामक व्यवस्था को सरल और युक्तिसंगत बनाना, औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना आदि कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। निजी और सार्वजनिक सम्पर्क को स्थापित व मजबूत करने के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 'औद्योगिक सलाहकार समिति' की स्थापना की जा चुकी है।

4. उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकासः राजस्थान में उद्योगों की प्रतिस्पर्घात्क क्षमता को बढ़ाने के लिए सड़के, अबाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल, उच्च क्षमता डाटा स्थानान्तरण को विकसित किया जाएगा। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, आधारभूत ढांचे के लिए कोष सर्जन, गैस ग्रिड का विकास, दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) के लाभ प्राप्त करना, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा प्रणाली आदि प्रयास होंगे। राज्य में विभिन्नसरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए तथा आधारभूत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वैधानिक शक्ति प्राप्त 'आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा। रीको अगले पांच वर्षों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 20000 एकड़ अतिरिक्त भूमि विकसित करेगा।

राजस्थान में एक दिसम्बर 2009 तक विद्युत संस्थापित क्षमता 7716 मेगावॉट की है। वित्त वर्ष 2013–14 तक लगभग 10000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की योजना है।

5. कौशल स्तरों और रोजगार योग्यता का विकास करनाः वैश्विक स्तर के उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधनों का होना आवश्यक है। राजस्थान के लोगों के लिए कौशल विकास और रोजगार योग्यता में सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी तथा वर्तमान आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरी और डिग्री कॉलेजों को प्रशिक्षण क्षमताओं से सुसज्जित किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलैन्सी' में बदला जाएगा तथा सेवारत प्रशिक्षण के लिए 'ट्रेन टू गेन' योजना लागू की जाएगी। रोजगार क्षेत्रों की आवश्यकतों के अनुसार वर्तमान प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक संस्थानों को अपनी रोजगार योग्यता में सुधार के लिए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। निर्धन और स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें संगठित क्षेत्र के लिए रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी रूप समुन्नत 'राजीव गांधी कौशल स्कूलों' की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं का सहयोग करेगी।

6. भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करनाः परियोजनाओं के लिए भूमि की त्वरित और आसान उपलब्धता निवेशकों की प्राथमिकता होती है। राजस्थान में अनुत्पादक और कम उर्वर भूमि की बहुतायत है। इसलिए राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए भूमि का लाभ संसाधन की तरह उठाया जा सकता है। राज्य में भूमि

की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन, भवन मानचित्र आदि के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। भू अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा भूमि बैंक का सृजन तथा निवेशों के लिए भूमि से लाभ प्राप्त करने के लिए नए नीतिगत दिशा निर्देशों का निरूपण जाएगा।

7. विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहनः राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कपड़ा, खनिज उत्पाद, हस्तकला, हथकरघा, रत्न और आभूषण जैसे कुछ क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से लाभपूर्ण स्थिति में है। औद्योगिक उत्पादन में भी इन क्षेत्रों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों के लिए राज्य में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ज्ञान क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनन एवं खनिज प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, कृषि व्यवसाय, वस्त्र एवं परिधान, हस्तकला एवं हथकरघा, निर्यात, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, हरित उद्योग, श्रम प्रधान क्षेत्र आदि विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेगी। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों जैसे खनन, पर्यटन आदि के लिए राजस्थान सरकार की पहले से ही विशिष्ट नीतियां है। ये नीतियां अबाध रूप से जारी रहेगी। नीतियों को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए इनकी समीक्षा की जाएगी। राजस्थान सरकार ज्ञान के विस्तार और उच्च कौशल आधारित गतिविधियों जैसे बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगी।

8. संकुल विकास (क्लस्तर डवलपमेंट): राजस्थान सरकार पूरे राज्य में एम.एस.एम.ई के संकुल विकास को प्राथमिकत देना जारी रखेगी। वर्तमान संकुलों को सुदृढ़ किया जाएगा और नये संकुलों को चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा। कम से कम 20 इकाइयों की संख्या वाले संकुल को विकसित करने के लिए नोडल संस्थान या औद्योगिक संघों को सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी भूमि को संकुलों की स्थापना के लिए बिना किसी परिवर्तन शुल्क के भूमि किस्म परिवर्तन की जाएगी। सरकारी भूमि पर बनने वाले संकुलों को सरकारी भूमि डी.एल.सी. दरों के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जाएगी। संकुल अंतिम बिंदु तक आधारभूत ढांचा सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। राजस्थान हथकरघा विकास निगम को मजबूत बनाने के लिए बुनकर समूहों को प्रशिक्षण की परियोजनाएं दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण प्रदान करने की एक विशेष योजना आरंभ करेगा।

सार रूप में देखें तो राजस्थान की नई औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति भारत में 1991 के बाद औद्योगिक संरचना में हुए क्रांतिकारी बदलाव के साथ राजस्थान के औद्योगिक वातावरण को समायोजित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल है। राज्य की इस नई औद्योगिक नीति में आधारभूत ढांचे और कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश के साथ सेवा क्षेत्र में भी निवेश प्रोत्साहित होगा। नई नीति राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

औद्योगिक विकास

राजस्थान अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहां की धरा ने स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, बॉगड़, पौद्दार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया है। इन्होंने देश और विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत में ख्याति अर्जित की है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त था। राज्य में बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास

संभव नहीं था। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2 प्रतिशत भाग ही पाया जाता है। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 वर्ष पूरे कर चुका है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचागत संरचना और आधारभूत सामाजिक सरचंना के विकास पर काफी बल दिया है। राज्य में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी है। विगत में केन्द्र सरकार ने यहां के कई जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार पिछड़े जिलों को सब्सिडी का लाभ मिला। राज्य सरकार यहां से पलायन कर गये उद्योगपतियों तथा देश–विदेश के अन्य उद्यमियों को राज्य में विनियोग बढ़ाने हेतु आकर्षित करके के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 23 व 24 सितम्बर, 2000 को जयपुर में 'अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मलेन–2000' का आयोजन किया गया। अब राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सन्तोषजनक होने के कारण बड़े उद्यमियों की मनोवृत्ति बदल रही है। उद्यमियों के कदम राज्य में निवेश के लिए बढ़ने लगे हैं। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन बहुतायत में उपलब्ध है। यहां विभिन्न उद्योगों के विकास की खूब संभावनाएं हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया जाए तो यह देश के औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों की श्रेणी में आ सकता है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग – राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग 2000–01 में 27.8 प्रतिशत था जो 2005–06 में बढ़कर 29. 7 प्रतिशत हो गया । वित्त वर्ष 2011–12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर कीमतों पर) उद्योग का भाग 29.85 प्रतिशत रहा है।

उद्योग वृद्धि दर – राजस्थान में खनन व विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2005–06 में 12.09 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। वित्त वर्ष 2008–09 में खनन व विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर घटकर 3.21 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) रह गई। वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

वैश्विक मंदी का राजस्थान पर प्रभाव – वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालाकि वैश्विक मंदी का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, किन्तु भारत की विकास दर 2008–09 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई जबकि यह 2007–08 में 9 प्रतिशत थी। भारत की औद्योगिक विकास दर 2008–09 में 2.6 प्रतिशत तक गिर गई।

स्थिर कीमतों (1999–2000) पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2005–06 में 6.70 प्रतिशत थी जो घटकर 2008–09 में 5.48 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 2008–09 में खनन व विनिर्माण वृद्धि दर 3.21 प्रतिश्त तक गिर गई। इससे स्पष्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी 2008 का अधिक प्रभाव पड़ा है।

पंजीकृत फैक्ट्रियां – राजस्थान में भारतीय फैक्ट्री एक्ट 1948 के अन्तर्गत सेक्शन 2 एम (i), सेक्शन 2 एम (ii) तथा सेक्शन 85 के अन्तर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियां है। राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9665 थी जो 2007 में बढ़कर 10001 हो गई।

लघु उद्योगों का विकास – अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार ने लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया हैं। लघु उद्योगों में काफी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में लघु उद्योगों की पंजीकृत इकाइयां 1975–76 में 20102 थी जो 2008–09 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई। लघु उद्योगों में 1975–76 में 1.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 2008–09 में बढ़कर 13.16 लाख हो गई। लघु उद्योगों में विनियोजित पूंजी 1975–76 में 72.37 करोड़ रूपए से बढ़कर 2008–09 में 8888.21 करोड़ रूपए हो गई।

खादी एवं ग्रामोद्योग – खादी एवं ग्रामोद्योग की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना, सहकारिता की भावना जागृत करना, कच्चा माल तथ आवश्यक औजारों की पूर्ति द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'फैशन फोर डवलपमेंट योजना' संचालित की जा रही है। राज्य में गुणवत्ता पूर्ण एवं आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008–09 में खादी का 18.14 करोड़ रूपए का उत्पादन एवं ग्रामोद्योग में 301.79 करोड़ रूपए का उत्पादन हुआ।

औद्योगिक उत्पादन – वर्तमान में राजस्थान में सूती एवं सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेन्ट, टेलीविजन, टायर टयूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइयां, खनिज आधारित बड़ी एवं मध्यम इकाइयां है। राजस्थान से मुख्य रूप से रत्न, आभू ाण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिक वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएं, रसायन, कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद है। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पादन इस प्रकार हैः– वर्ष 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57480 टन, खाद्य तेल 120866 टन, सूती कपड़ा 203.40 लाख मीटर, सिथेंटिक तागा 536. 60 लाख कि.ग्रा., यूरिया 371883 टन, सल्फ्यूरिंक एसिड़ 594045 टन, सीमेन्ट 101.20 लाख टन, वाटर मीटर 89592 आदि।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है जिन्हें 'डीम्ड फोरेन टेरिटरी' का दर्जा देते हुए सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है।

राजस्थान में सीतापुरा (जयपुर) में जैम्स एवं ज्वैलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है। जयपुर में रीको और महिन्द्रा लाईफ स्पेस डवलपर लिमिटेड द्वारा जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पॉर्टनरशिप (पीपीपी) के अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास ने अब गति पकड़ ली है। राज्य में आधारभूत संरचना के सुधर जाने से अब आई.टी. क्षेत्र की दिग्गज कम्पनियां जैसे इनफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टेक महिन्द्रा, नगारो आदि राज्य में निवेश में रूचि दिखा रही है।

कृषि विकास

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.07 प्रतिशत है। यह ग्रामीण जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि मानसून से प्रभावित है। यहां मानसून की प्रकृति साधारणतया अनियमित एवं अनिश्चित है। राजस्थान में मानसून विलम्ब से आता है और जल्दी चला जाता है। यहां मानसून की अवधि लगभग तीन माह ही है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थिति से भारी क्षति होती है। वित्त वर्ष 2008–09 में 12 जिलों के 7402 गांवों की 100 लाख जनसंख्या अकाल और अभाव से प्रभावित हुई । इस वर्ष 47.7 लाख रूपये का भू–राजस्व निलंबित किया गया।

राजस्थान का भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 2008 में 34270 हजार हैक्टेयर था। इसमें सकल कृषिगत क्षेत्र 22208 हजार हैक्टैयर था जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.80 प्रतिशत था। राज्य में 2007–08 में विभिन्न स्त्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8088 हजार हैक्टैयर था जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान – किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग और सेवाएं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। वित्त वर्ष 2005–06 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 27.52 प्रतिशत, उद्योग का योगदान 29.72 प्रतिशत तथा सेवाओं का योगदान 42.76 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.09 प्रतिशत, उद्योग का योगदान 29.85 प्रतिशत तथा सेवाओं का योगदान 48.60 प्रतिशत था। पिछले कुछ वर्षो में (2008–09 से 2011–12) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को देखे तो पाते हैं कि स्थिर कीमतों (2004–2005) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 22 प्रतिशत स्थिर सा हो गया है।

कृषि वृद्धि दर – कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे कारण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र वृद्धि दर 2005–06 में ऋणात्मक 0.88 प्रतिशत थी। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र वृद्धि दर 2008–09 में बढ़कर 6. 12 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) हो गई।

राजस्थान की प्रमुख फसलें

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यहां विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। राज्य में रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम तथा खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, चावल, मूँग, मोठ, अरहर, सूरजमुखी आदि मुख्य है।

खाद्यान्न उत्पादन

योजनाबद्ध विकास में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहां खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भर होना है। खाद्यान्न उत्पादन 1960–61 में 45.41 लाख टन था जो बढ़कर 1990–91 में 109.35 लाख टन हो गया। खाद्यान्न का उत्पादन 2011–12 में और बढ़कर 209.45 लाख टन (प्रावधानिक) हो गया।

खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दालों के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ प्रमुख फसलें है। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश के कुल बाजरा उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में होता है। देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में होता है। देश में उत्तरप्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन राजस्थान में होता है।

राजस्थान में 2008–09 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन, दलहन उत्पादन 18.98 लाख टन, इन दोनो को मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 159.53 लाख टन (संभावित) था।

तिलहन - देश में खाद्य तेलों का अभाव है। खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा भण्डार खर्च होते है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान ''तिलहन क्रान्ति'' की ओर अग्रसर हुआ है। राज्य में मूंगफली , तिल, सोयाबीन, राई व सरसों, अलसी, तारामीरा का उत्पादन होता है।

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1960–61 में 1.72 लाख टन था जो 1990–91 में बढ़कर 23.56 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 2007–08 के 42.29 लाख टन की तुलना में 2008–09 में 55.36 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 30.91 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसल में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी तथा रबी फसल में राई व सरसों, तारामीरा व अलसी सम्मिलित है।

गन्ना – गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़

आदि जिलों में होता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है। गन्ने का उत्पादन 2007–08 में से 5.94 लाख टन की तुलना में 2008–09 में 3.02 लाख टन होने की संभावना है जो 49.16 प्रतिशत कमी दर्शाता है।

कपास – कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में कपास विशेषतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोई जाती है। कपास का उत्पादन 2007–08 में 8.62 लाख गॉठे था जबकि 2008–09 में 7.26 लाख गॉठें उत्पादित होने की संभावना है जो 15.78 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

फल, सब्जियॉ और मसालें – राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद, सन्तरे हैं। सब्जियों में आलू व प्याज का उत्पादन होता है। इनके अलावा यहां जायकेदार मसालों का भी उत्पादन होता हैं। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाईन, मैथीं, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन का उत्पादन होता है।

राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं

राजस्थान योजनाबद्ध विकास के बासठ वर्ष पूरे कर चुका है। इस समयावधि में दस पंचवर्षीय योजनाएं, छह वार्षिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन मे है। सबसे महत्तपूर्ण बात यह है कि 1951–52 से लेकर 2006–07 तक के योजनाबद्ध विकास में 74651 करोड़ स्पष्ट व्यय किये जा चुके हैं। राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में कुछ बड़ी बाधाएं हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है :

1. **मरूस्थल** – राजस्थान में मरूस्थल आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। राज्य के कुल भू–भाग का 61.11 प्रतिशत भाग रेत के धोरों से पटा हुआ है। राज्य के पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 11 जिलों में राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या थार मरूस्थल में निवास करती है। रेत के समुद्र में प्रदेशवासी कठोर जीवन जीते हैं।

2. **मानसून पर निर्भरता** – राज्य में कृषि मानसून पर निर्भर है। हालांकि योजनाबद्ध विकास में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, किन्तु अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को देखते हुए सिंचाई संसाधनों का आज भी कमी है। कृषि उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन के घटने–बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी पड़ जाती है।

3. **अकाल** – राज्य में अकाल और सूखा आर्थिक विकास में बाधा बना हुआ है। राज्य में अकाल काले नाग की भांति डैने फैलाए पसरा है। राजस्थान अतीत में भी अकाल की चपेट में रहा। वर्तमान में भी अकाल से निजात नहीं मिला है। वर्ष 1981–82 से लेकर 2008–09 तक 27 वर्षों में केवल 1983–84, 1990–91, 1994–95 तीन वर्ष ही ऐसे रहे जब राज्य को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। शेष सभी वर्षों में न्यूनाधिक अकाल की स्थिति थी। वर्ष 1991–92 और 2002–03 में पूरा प्रदेश अकाल की भयंकर चपेट में था। वर्ष 2008–09 में भी 12 जिलों के 7402 गॉवों की एक करोड़ जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी। इस वर्ष 47.7 लाख रूपए भू–राजस्व निलंबित किया गया।

4. **पानी की कमी** – राजस्थान पानी की कमी वाला राज्य है। यहां सतही जल एवं भूमिगत जल दोनों दुर्लभ संसाधन है। कई स्थानों में भूमिगत जल मानव एवं पशुओं दोनों के उपयोग के अनुकूल नहीं है। प्रदेश का बड़ा भाग मरूथल, ऊपर से मानसून की अनिश्चितता फिर अकाल से मरू प्रदेश के बाशिंदों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। सतत् प्रवाही नदियों के बावजूद पूर्वी राजस्थान भी पेयजल समस्या से अछूता नहीं है। राज्य में साफ एवं सुरक्षित पेयजल जटिल समस्या है। राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए प्रयत्नशील है। अगर राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो यह भविष्य में आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बन सकता है।

5. **अधिक जनसंख्या** – राजस्थान अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है। गुणात्मक जनसंख्या का अभाव है। अधिक जनसंख्या विकास में बाधा है। राजस्थान की जनसंख्या 1951 से सभी

जनगणनाओं में बहुत तेज गति से बढ़ी है। राजस्थान की जनसंख्या 1991 में 4.40 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 6.86 करोड़ हो गई। राजस्थान की जनसंख्या की 2001 में दशकीय वृद्धि 28.41 प्रतिशत थी जो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 21.34 प्रतिशत से अधिक थी। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत भाग निवास करता है। अधिक जनसंख्या से राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या मुखर हो गयी है।

6. **कम साक्षरता** – राजस्थान जनसंख्या में आगे तथा साक्षरता में पीछे है। महिला साक्षरता में स्थिति चिन्ताप्रद है, हालांकि राज्य में साक्षरता में 1991 की तुलना में 2011 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। राज्य में 2011 में साक्षरता दर 67.1 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता 80.5 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 52.7 प्रतिशत थी।

7. **उर्जा की कमी** – उर्जा महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उर्जा विकास से ही आर्थिक विकास संभव है। उर्जा के अभाव में औद्योगिक विकास महज कल्पना है। राजस्थान में उर्जा की कमी है। यहां उर्जा की मांग और पूर्ति में अंतराल है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग भी कम है।

8. **कम पूंजी निवेश** – कम पूंजी निवेश आर्थिक विकास में बाधा रहा है। हालांकि राजस्थान में जन्में औद्योगिक घरानों ने देश–विदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, किन्तु राजस्थान में यहां के मूल उद्यमियों का निवेश अपेक्षित नहीं रहा। योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का खूब विकास हुआ, किन्तु राजस्थान में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कम है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगों का लगभग 2 प्रतिशत अंश ही पाया जाता है। वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका घट गई है। राजस्थान आर्थिक उदारीकरण के दौर में विदेशी निवेशकों को अधिक आकर्षित नहीं कर सका है।

राजस्थान में आर्थिक विकास की संभावनाएं

विकासशील देशों में अग्रणी भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान आर्थिक और सामरिक दृष्टि से देश का महत्त्वपूर्ण राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। थार मरूस्थल के कारण राजस्थान की विशेष पहचान है। हालांकि राज्य का अधिकांश भाग रेत के धोरों से पटा हुआ है, किन्तु यह धोरे रूपी सागर अपने में अथाह संपदा समेटे हुए हैं। राजस्थान ने आर्थिक सुधारों को आत्मसात कर देश की प्रगति के साथ कदमताल की है। वर्तमान में राज्य में विदेशी पूंजी आकर्षित होने लगी है।

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहां आर्थिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। राजस्थान में आर्थिक विकास की भावी संभावनाएं निम्नांकित है :

1. **खनिजों की प्रचुरता** – राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। यहां विविध प्रकार के खनिज पाये जाते हैं। कुछ खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान में ही होता है। राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश में अग्रणी है।

राजस्थान में धात्विक खनिजों में ताँबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैगनीज, चांदी, टंगस्टन, आणविक खनिज तथा अधात्विक खनिजों में अभ्रक, जिप्सम, राक फास्फेट, लाइम स्टोन (चूना पत्थर), सोप स्टोन, संगमरमर व ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, पाइराइट्स, बेन्टोनाइट, पन्ना व गारनेट, चायना क्ले व व्हाइट क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैण्ड पाये जाते है। इनके अलावा खनिज ईंधन में लिग्नाइट राज्य में उपलब्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

राजस्थान का अधात्विक खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। खनिज सम्पदा की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थान का ही नाम आता है। राजस्थान जिप्सम, सीसा, जस्ता, रॉक फास्फेट, मैगनीज, चाँदी, एस्बेस्ट्स फेल्सपार आदि के उत्पादन में देश में अग्रणी है।

2. नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च,

नई दिल्ली ने राजस्थान का टैक्नो–इकोनॉमिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगों की क्षमता और भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निम्नांकित उद्योगों की स्थापना का औचित्य बताया– ट्रैक्टर व संबंधित यंत्र, डीजल ईंजन, स्कूटर व मोटर साइकिलें, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, विद्युत सामग्री, इस्पात के तार, पाइप, टयूब, कीलें, नट बोल्ट, पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, सफेद व रंगीन सीमेन्ट, कांच, तेल शोधक आदि कारखाने।

3. राजस्थान में निम्नांकित उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं :

(i) कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का संयंत्र लगाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(ii) उदयपुर में एक पिग लोहा संयंत्र लगाने की आवश्यकता है जहां निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) सवाई माधोपुर में लाइम स्टोन (सीमेंटग्रेड) के भरपूर भण्डार है इन भण्ड़ारों के उपयोग के लिए सीमेंट उद्योग को चालू कर इन भण्डारों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

(iv) निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बोर्ड बनाये जा सकते है।

(v) उत्तम सेलेनाइट के भण्डारों का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य उद्योगों का विकास करने में किया जाना चाहिए।

(vi) फेल्सपार क्वार्टस व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानों की स्थापना का क्षेत्र बढ़ सकता है।

(vii) सिलिका के उपयोग से कांच के उद्योग का विस्तार किया जा सकता है।

4. **खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के विपुल भण्डार** – राजस्थान में 1984 में जैसलमेर के सादेवाला क्षेत्र में खनिज तेल तथा जुलाई 1990 में डांडेवाला (जैसलमेर) में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार मिले थे। वर्ष 1983 में जैसलमेर के घोटारू नामक स्थान पर गैस के भण्डार प्राप्त हुए थे।

राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में मौजूदा अनुमानों के अनुसार 6.5 अरब बैरल तेल के भण्डार है। ऐसे में 2011 के अंत तक प्रदेश के चिन्हित तेल क्षेत्रों से 2.40 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन की उम्मीद है। केयर्न इण्डिया के अनुसार 2011 तक राजस्थान देश के सकल घरेलू तेल उत्पादन का चौथाई से भी बड़ा हिस्सा मुहैया करने लगेगा। बाड़मेर में मंगला, भाग्यम, एश्वर्या व अन्य क्षेत्रों के कुल 196 तेल कुओं में उत्खनन शुरू हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में खनिज तेल की विपुल उपलब्धता को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल रिफाइनरी की स्थापना की सम्भावना है, राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है।

5. **कृषि संपदा पर आधारित उद्योग** – कृषि संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य में कपास, गन्ना, तिलहन, मक्का, चना व गेहूँ आदि ऐसी फसलें हैं जिन पर आधारित अनेक छोटे बड़े उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषिगत उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2005–06 में 108.24 लाख टन था जो 2011–12 में बढ़कर 209.45 लाख टन (प्रावधानिक) हो गया।

पिछले वर्षों में राजस्थान तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग राजस्थान में होने लगा है। सरसों के उत्पादन में यह एक अग्रणी राज्य हो गया है। यहां देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35 प्रतिशत अंश होने लगा है।

राज्य में जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, डूंगरपुर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किये जा सकते है। कोटा, भरतपुर व उदयपुर में चीनी की मिलें लगाई जा सकती है। कोटा में वनस्पति घी का उद्योग तथा भरतपुर, अलवर, गंगानगर, सवाई माधोपुर में खाद्य तेल मिलें स्थापित की जा सकती है। पूरे राज्य में मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किये जा सकते है।

6. **पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग** – राज्य में चमड़ा, ऊन, मांस, दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश के नगरों में चमड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग, दूध पाऊडर के उद्योग, मक्खन, पनीर व पशु आहार के उद्योगों की स्थापना की विपुल संभावनाएं हैं। बीकानेर व जोधपुर में होजरी, ऊनी व चमड़े के कारखाने, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर में हड्डी पीसने के कारखानें तथा अलवर व उदयपुर में मछली उद्योग का विकास किया जा सकता है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 579 लाख पशुधन तथा 50.12 लाख से अधिक कुक्कुट सम्पदा है। वर्ष 2008–09 में राज्य में कुल दूध का उत्पादन 9,942 हजार टन था। राज्य के पश्चिमी जिलें स्वदेशी पशुधन के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य पशुधन उत्पाद दूध, मांस, अण्डे व ऊन है।

7. **वनों पर आधारित उद्योग** – राजस्थान में हालांकि वन क्षेत्र कम है। यहां वन 2006–07 में भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.87 प्रतिशत ही है, किन्तु यहां वनोत्पाद में विविधता है फिर राजस्थान सरकार वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस दिशा में 'हरित राजस्थान' कार्यक्रम उल्लेखनीय है।

राज्य में वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में दियासलाई उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा साफ करने का उद्योग, बीड़ी उद्योग, खस आधारित उद्योग आदि स्थापित किये जा सकते हैं।

8. **आधारभूत संरचना** – क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान में हाल के वर्षों में आधारभूत संरचना का खूब विकास हुआ है। राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में आधारभूत संरचना पर भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किये है। केन्द्र सरकार भी राजस्थान में आधारभूत संरचना के विकास के लिए रूचि ले रही है।

राज्य में उर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसम्बर 2011 तक 9831 मेगावाट थी। राज्य में अक्षय ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है। अच्छी सड़कें विकास की जीवन रेखा है। वर्ष 2008–09 में राज्य में निर्मित सड़कों का कुल लम्बाई 1,86,806 किलोमीटर थी। इनके अलावा राजस्थान संचार, बैंकिग, शिक्षा, चिकित्सा, आवास आदि क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है। आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में सहायक है।

9. **उद्यमी** – राजस्थानी मूल के उद्यमियों ने देश और विदेश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाई है। लक्ष्मी निवास मित्तल, बिड़ला, पौद्दार, गोलेछा, साहू आदि बड़े उद्यमी है। यदि ये चाहे तो राज्य के आर्थिक कायाकल्प में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

10. **औद्योगिक विकास के निगम** – राजस्थान में औद्योगिक विकास का वातावरण बनाने में अनेक निगम भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। रीको का मुख्य उद्देश्य राजस्थान का योजनाबद्ध तीव्र विकास करना है। राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार और नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना, सहकारिता की भावना पैदा करना एवं कच्चे माल व आवश्यक औजारों की पूर्ति द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है।

राजस्थान में विद्यमान प्राकृतिक संपदा का विवेकपूर्ण दोहन किया जाए तो राजस्थान देश के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार केन्द्र से राज्य को विशेष दर्जा देने हेतु प्रयत्नशील है जिससे अधिकाधिक वित्तिय संसाधन प्राप्त हो सकें और आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित की जा सके।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत हुई –
   (अ) 1955–56 (ब) 1951–52
   (स) 1991–92 (द) 1966–69

2. राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित उद्व्यय है–
(अ) 33735 करोड़ रूपए (ब) 19567 करोड़ रूपए
(स) 11999 करोड़ रूपए (द) 71732 करोड़ रूपए
3. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि है–
(अ) 1956–61 (ब) 1961–66
(स) 1951–56 (द) 1969–74
4. राज्य की दसवीं योजना में मद पर सबसे अधिक व्यय किया गया–
(अ) सिंचाईं व बाढ़ नियंत्रण (ब) ग्रामीण विकास
(स) सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं (द) उर्जा
5. राज्य में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई–
(अ) एक अप्रैल 2006 (ब) एक अप्रैल 2009
(स) एक अप्रैल 2007 (द) एक अप्रैल 2008
6. राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लक्ष्य है–
(अ) 9 प्रतिशत (ब) 7.4 प्रतिशत
(स) 8 प्रतिशत (द) 9.9 प्रतिशत
7. राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास शीर्ष पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किया गया है–
(अ) परिवहन (ब) कृषि एवं संबद्ध सेवाएं
(स) उद्योग व खनिज (द) उर्जा
8. राजस्थान की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है–
(अ) 2007–08 (ब) 2008–09
(स) 2009–10 (द) 2010–11
9. राज्य में 2011–12 में खाद्यान्न उत्पादन (प्रावधानिक) था–
(अ) 108.2 लाख टन (ब) 109.3 लाख टन
(स) 202.07 लाख टन (द) 149.3 लाख टन
10. चोपंकी (भिवाड़ी) विशेष औद्योगिक समूह है–
(अ) जैक्स एण्ड ज्वैलरी (ब) होजरी
(स) टेक्सटाइल्स (द) दस्तकारियां
11. राजस्थान में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र वृद्धि दर ऋणात्मक रही –
(अ) 2005–06 (ब) 2006–07
(स) 2008–09 (द) 2007–08
12. भारत में अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है–
(अ) द्वितीय (ब) चतुर्थ
(स) प्रथम (द) तृतीय
13. मंगला प्रसिद्ध है–
(अ) ताबां (ब) तेल कुएं
(स) दुग्ध उत्पादन (द) लोह अयस्क

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवी पंचवर्षीय योजना तक कुल वास्तविक व्यय कितना है?
2. प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस विकास क्षेत्र को दी गई?
3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है?
4. राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 का आकार कितना है?
5. राज्य में दिसम्बर 2011 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि बताइये।
2. दसवीं पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य थे?
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक लक्ष्य बताइये।
4. योजनाबद्ध विकास की कोई तीन उपलब्धियां बताइये।
5. राजस्थान की औद्योगिक नीति 2010 के लक्ष्य लिखिए।
6. पांच विशेष औद्योगिक समूह के नाम बताइये।
7. राजस्थान के आर्थिक विकास में क्या बाधाएं है?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्व्यय की व्याख्या कीजिए।
2. राजस्थान में योजनाबद्ध विकास की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
3. भारत की नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है?
4. राजस्थान की जून 2010 की औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए।
5. राजस्थान के औद्योगिक विकास पर टिप्पणी कीजिए।
6. राजस्थान में कृषि की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
7. राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बताइये।

□□□